भी सहायता प्रदान करता है, जिसके अन्तर्गत लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(च) और (छ) चूंकि ये सब असीमित अवधि वाली योजनाएं हैं, इसलिए सभी पात्र प्रस्तावों पर सिडबी द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान सहायता प्रदान की जायेगी और इन योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के दौरान इसके द्वारा कोई विशेष आबंटन नहीं किया गया है।

वित्तीय क्षेत्र का पुनर्गठन

61. **श्री अजीत जोगी :**
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग प्रणाली के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजित अध्ययन में यह स्वीकार किया गया है कि इस क्षेत्र में सुधारों की सफलता को सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय समायोजन की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के पुनर्गठन के संबंध में अन्य कौन-सी महत्वपूर्ण सिफारिशें की गयी हैं; और

(ग) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसे किसी अध्ययन का प्रायोजन नहीं किया है। अलबत्ता, वित्त मंत्रालय ने श्री डी. खटखरे को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था जो इस समय परीक्षणाधीन है।

Manipulation of law by Foreign Banks

62. SHRI M. A. BABY:
SHRI E. BALANANDAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that foreign banks are still indulging in manipulation of law of the land with regard to Vostro accounts and siphoning off hundreds of crores of rupees every month;

(b) if so, how many such cases have been detected: and

(c) the action taken in those cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) Enforcement Directorate has intimated that during the period December 1992 to May 1993, it had investigated 40 illegal transactions through various banks involving a total amount of Rs. 77.9 crores in which non-convertible Rupee funds emnating from the Bank for Foreign Economic Affairs of the erstwhile U.S.S.R. were credited to the Vostro A|cs of various foreign banks held with banks in India. All these transactions pertained to the period January, 1991 to September, 1992. After completion of investigations Show Cause Notices have been issued to the banks concerned and their officers during the period June, 1993 to February, 1994. Also sanction to prosecute has been issued under Section 56 of F.E.R.A., 1973 in respect of all these transactions.

Enforcement Directorate has further intimated that in December, 1994 certain documents seized by C.B.I., Bombay in August, 1994 in connection with an investigation being conducted by them in another matter were handed over to the Enforcement Directorate. These documents have